

सत्यमेव जयते

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

साप्ताहिक सूचना पत्र

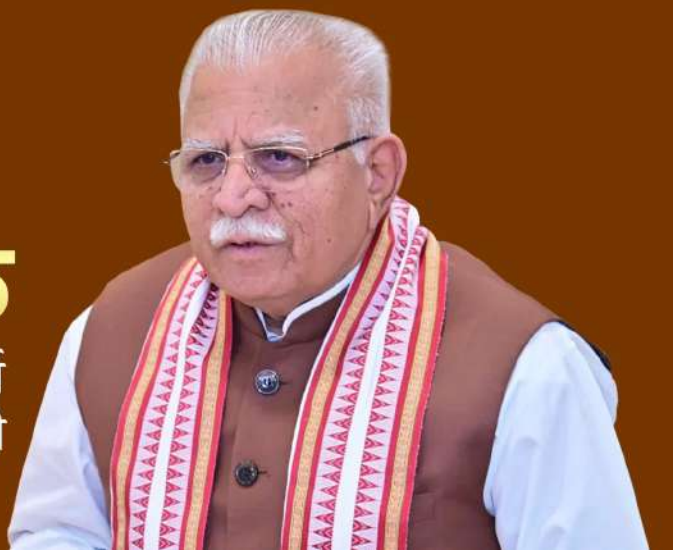
दिनांक 23.10.2026 से 29.10.2026

8वाँ संस्करण



श्री मनोहर लाल

माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य
तथा विद्युत मंत्री



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. शहरी परिवहन के रूपांतरण के लिए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल का '3-I' मंत्र: Integration, Inclusiveness और Intelligence पर जोर

2. विकसित भारत के लक्ष्य के लिए शहरों का समग्र विकास आवश्यक: श्री मनोहर लाल

3. शहरों के रूपांतरण को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्री ने राज्य मंत्रियों और महापौरों के साथ की बैठक

4. MoHUA ने National Urban Conclave 2026 में अपशिष्ट प्रबंधन पर दो एडवाइजरी और 'स्वच्छता के सुपरहीरो' पुस्तक की शुरुआत की

5. केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 18 शहरों के लिए स्ट्रीट फूड हब निधि की पहली किस्त जारी की

साप्ताहिक सूचना पत्र

23.10.2026 से 29.10.2026

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

6 National Urban Conclave 2026 में PMAY-U के तहत तीन महत्वपूर्ण पहलों और प्रकाशनों का शुभारंभ

7 त्रिपुरा के 278 परिवारों के सपनों को मिला अपना आशियाना, Light House Project के दो ब्लॉकों का उद्घाटन

8 शहरी परिवहन को मिलेगी नई गति: ओडिशा में PM-eBus Sewa की शुरुआत

9 DMRC को 19वें Urban Mobility India Conference में प्रतिष्ठित 'Award of Excellence' से सम्मानित किया गया

10 National Urban Conclave एवं Urban Mobility India सम्मेलन में NBCC ने प्रदर्शित की शहरी विकास विशेषज्ञता

साप्ताहिक सूचना पत्र

23.10.2026 से 29.10.2026

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

24 अक्टूबर, 2026

शहरी परिवहन के रूपांतरण के लिए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल का '3-I' मंत्र: Integration, Inclusiveness और Intelligence पर जोर



19वें Urban Mobility India Conference-cum-Exhibition 2026 के समापन सत्र में माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने भाग लिया और संबोधित किया। सम्मेलन की थीम 'Urban Accessibility and Liveability in the Digital Age' थी।

अपने संबोधन में मंत्री ने भारत के विकास में शहरी परिवहन की बदलती भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि पहले बेहतर परिवहन को विकास के परिणाम के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यह आर्थिक विकास और शहरी रूपांतरण का एक बुनियादी आधार बन गया है।

भारत में शहरी परिवहन के बदलते स्वरूप पर जोर देते हुए श्री मनोहर लाल ने Integration, Inclusiveness और Intelligence (3-I) को भविष्य के लिए तैयार शहरी परिवहन प्रणालियों के प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने निर्बाध कनेक्टिविटी, सुलभ एवं समावेशी सार्वजनिक परिवहन तथा स्मार्ट तकनीकों को अपनाने के महत्व पर बल दिया, ताकि शहरों को अधिक टिकाऊ, कुशल और रहने योग्य बनाया जा सके।

कार्यक्रम में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री ने शहरी परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देते हुए विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।

श्री मनोहर लाल ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को शुभकामनाएँ दीं। सम्मेलन में हुई चर्चाओं और सम्मान समारोह ने देशभर में सुलभ, समावेशी एवं टिकाऊ शहरी परिवहन प्रणालियों के विकास में नवाचार, प्रौद्योगिकी और एकीकृत मोबिलिटी समाधानों के महत्व को रेखांकित किया।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

25 अक्टूबर, 2026

विकसित भारत के लक्ष्य के लिए शहरों का समग्र विकास आवश्यक: श्री मनोहर लाल





माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने 24 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर, ओडिशा में 'Urban Rising: Rethinking Urban Systems, Solutions and Delivery' थीम के तहत आयोजित National Urban Conclave 2026 के समापन सत्र में भाग लिया और संबोधित किया।

अपने संबोधन में मंत्री ने भारत में शहरीकरण के बदलते स्वरूप को रेखांकित करते हुए कहा कि अब शहरों का विकास केवल ऐतिहासिक, धार्मिक या औद्योगिक केंद्रों के आसपास ही नहीं हो रहा है, बल्कि वे तेजी से राजमार्गों, हवाई अड्डों और आधुनिक परिवहन कॉरिडोर के आसपास भी विकसित हो रहे हैं।

उन्होंने जोर दिया कि शहरी विकास का उद्देश्य केवल अवसंरचना का निर्माण करना नहीं, बल्कि शहरों को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और बेहतर जीवन गुणवत्ता के सशक्त केंद्रों में बदलना है।

वर्ष 2014 के बाद से भारत की शहरी विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि अब विकास का दायरा सड़क, आवास और बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़कर एकीकृत दृष्टिकोण तक विस्तृत हुआ है, जिसमें नागरिकों को शहरी नियोजन के केंद्र में रखते हुए स्थिरता, समावेशिता और बेहतर जीवन-योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

माननीय मंत्री ने राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) से सम्मेलन में सामने आए महत्वपूर्ण सुझावों को ठोस कार्ययोजनाओं में बदलने तथा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

25 अक्टूबर, 2026

शहरों के रूपांतरण को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्री ने राज्य मंत्रियों और महापौरों के साथ की बैठक



द्वितीय National Urban Conclave 2026 के दौरान माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने शहरी विकास के क्षेत्र में प्रमुख प्राथमिकताओं और भारत के शहरों के रूपांतरण को गति देने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों और महापौरों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में Urban Challenge Fund, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U), अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) और स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (SBM-U) सहित प्रमुख शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर चर्चा की गई।

इस दौरान शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, आवश्यक नागरिक सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा तेजी से बढ़ते शहरों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नई पहलों और सहयोगात्मक रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

शहरी विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग पर विशेष जोर दिया गया।

यह बैठक विभिन्न पक्षों के विचारों के आदान-प्रदान और प्राथमिकताओं की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। इसका उद्देश्य भारत के परिवर्तनकारी शहरी विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप अधिक रहने योग्य, टिकाऊ, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरों का निर्माण करना है।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

25 अक्टूबर, 2026

MoHUA ने National Urban Conclave 2026 में अपशिष्ट प्रबंधन पर दो एडवाइजरी और 'स्वच्छता के सुपरहीरो' पुस्तक की शुरूआत की

National Urban Conclave 2026 के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने शहरी भारत में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कीं। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे।

श्री मनोहर लाल ने निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कचरा प्रबंधन पर एडवाइजरी जारी की। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को 'C&D कचरा प्रबंधन नियम, 2025' के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना है। इसमें कचरे के आकलन, रीसाइक्लिंग, उपयोग की योजना, खरीद प्रक्रियाओं, धूल नियंत्रण और रीसाइकल की गई सामग्रियों के पुनः उपयोग के संबंध में व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया है। साथ ही, नए नियामक ढांचे के तहत विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।

MoHUA ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत थोक अपशिष्ट उत्पादकों पर एक अन्य एडवाइजरी भी जारी की। यह एडवाइजरी ULBs और थोक अपशिष्ट उत्पादकों को स्रोत पर कचरे का पृथक्करण तथा वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन मजबूत करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है। इसमें विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व (EBWGR) का ढांचा प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, जवाबदेही और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए पंजीकरण, अनुपालन, निगरानी, प्रमाणन और प्रवर्तन तंत्र पर मार्गदर्शन दिया गया है।

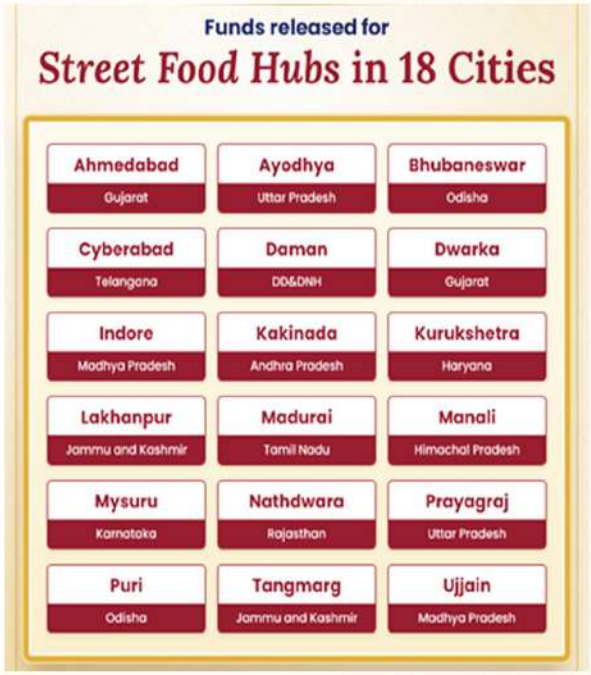
युवा नागरिकों में व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की दिशा में MoHUA ने 'स्वच्छता के सुपरहीरो' नामक बच्चों की पुस्तक भी प्रस्तुत की। इस पुस्तक का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता, कचरे का पृथक्करण, रीसाइक्लिंग और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता विकसित करना है। रोचक कहानियों, रंगीन चित्रों और इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से यह पुस्तक बच्चों को कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया से परिचित कराती है और शहरों को स्वच्छ रखने में सफाई मित्रों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। यह पहल बच्चों को स्वच्छता एवं स्थिरता का दूत बनकर अपने परिवारों और समुदायों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करने का संदेश देती है।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

25 अक्टूबर, 2026

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 18 शहरों के लिए स्ट्रीट फूड हब निधि की पहली किस्त जारी की



25 अक्टूबर 2026 को माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित National Urban Conclave 2026 के दौरान 18 चयनित शहरों के लिए स्ट्रीट फूड हब पहल के अंतर्गत निधि की पहली किस्त जारी की।

इस पहल के तहत चयनित 18 शहर हैं—अहमदाबाद (गुजरात), अयोध्या (उत्तर प्रदेश), भुवनेश्वर (ओडिशा), साइबराबाद (तेलंगाना), दमन (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव), द्वारका (गुजरात), इंदौर (मध्य प्रदेश), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), लखनपुर (जम्मू और कश्मीर), मदुरै (तमिलनाडु), मनाली (हिमाचल प्रदेश), मैसूरु (कर्नाटक), नाथद्वारा (राजस्थान), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), पुरी (ओडिशा), तंगमर्ग (जम्मू और कश्मीर) तथा उज्जैन (मध्य प्रदेश)।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 13 अप्रैल 2026 को PM SVANidhi योजना के तहत शुरू की गई स्ट्रीट फूड हब पहल का उद्देश्य देशभर में अधिकतम 50 सुव्यवस्थित, स्वच्छ और आवश्यक सुविधाओं से युक्त वेंडिंग स्थलों का विकास करना है। शहरी विकास विभाग द्वारा अभिसरण (Convergence) दृष्टिकोण के माध्यम से लागू की जा रही इस पहल का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका को सुदृढ़ करना, स्थानीय खान-पान की विरासत को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना तथा विशेष रूप से अधिक पर्यटन क्षमता वाले शहरों में टिकाऊ फूड डेस्टिनेशन विकसित करना है। FSSAI द्वारा वेंडर्स को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक स्ट्रीट फूड हब के लिए अधिकतम ₹4 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, City Street Vending Plan को अधिसूचित करने पर ₹25 लाख का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

24 अक्टूबर, 2026

National Urban Conclave 2026 में PMAY-U के तहत तीन महत्वपूर्ण पहलों और प्रकाशनों का शुभारंभ





ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित National Urban Conclave 2026 के उद्घाटन सत्र में ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पहलों और प्रकाशनों का शुभारंभ किया गया।

1. E-book: 'मेरा घर, मेरा अभिमान'

यह ई-पुस्तक PMAY-U और PMAY-U 2.0 के लाभार्थियों की प्रेरक जीवन-यात्राओं का संकलन है। इसमें उन परिवारों की कहानियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनका जीवन असुरक्षित आवासीय परिस्थितियों से निकलकर सुरक्षित और पक्के घर मिलने से बदला है। यह पुस्तक दर्शाती है कि बेहतर आवास ने परिवारों को गरिमा, सुरक्षा और आशा प्रदान करने के साथ महिलाओं को सशक्त बनाया, परिवारों को मजबूत किया और उज्ज्वल भविष्य के नए अवसर खोले हैं।

2. PMAY-U 2.0 पुरस्कार 2027

National Urban Conclave 2026 के दौरान PMAY-U 2.0 पुरस्कार 2027 की मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) जारी की गई। इन पुरस्कारों का उद्देश्य किफायती आवास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन, नवाचार और बेहतर कार्यप्रणालियों को मान्यता देकर आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

इनके माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बेहतर परिणाम हासिल करने, जवाबदेही बढ़ाने तथा किफायती आवास के क्षेत्र में नवाचारपूर्ण, व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले और अनुकरणीय समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रयासों और उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए ये पुरस्कार प्रदर्शन में सुधार, नवाचार और हितधारकों के बीच ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देंगे तथा 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे।







3. PMAY-U 2.0: 'घर तक जानकारी'

PMAY-U 2.0 के तहत लाभार्थियों से सीधे संवाद को सुदृढ़ करने और आवास सेवाओं की उपलब्धता में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बहुभाषी डिजिटल संचार व्यवस्था शुरू की गई है। इसके प्रमुख घटक हैं:

क. बहुभाषी SMS सूचनाएँ: आवास प्राप्ति की प्रक्रिया के सात प्रमुख चरणों पर लाभार्थियों को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में SMS अलर्ट भेजे जा रहे हैं, ताकि उन्हें अपनी पसंदीदा भाषा में आवास संबंधी जानकारी समय पर मिल सके।

ख. BHASHINI के साथ एकीकरण: बहुभाषी संचार को सुगम बनाने और डिजिटल सेवाओं की सुलभता बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल को BHASHINI के साथ एकीकृत किया गया है।

ग. सुरक्षित लाभार्थी सत्यापन: लाभार्थियों की सुरक्षित और विश्वसनीय पहचान सुनिश्चित करने के लिए सहमति-आधारित Aadhaar e-KYC की व्यवस्था शामिल की गई है।

घ. पारदर्शिता और जवाबदेही: स्वीकृत लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई है, जबकि आधार विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जाता है।

यह पहल अंतिम छोर तक सूचना की पहुँच में आने वाली कमियों को दूर करने, लाभार्थी-केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है कि आवास संबंधी जानकारी लाभार्थियों तक समय पर, सुलभ रूप में और उनकी अपनी भाषा में पहुँचे।







Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

29 अक्टूबर, 2026

त्रिपुरा के 278 परिवारों के सपनों को मिला अपना आशियाना, Light House Project के दो ब्लॉकों का उद्घाटन



'सबके लिए आवास' के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) के तहत अगरतला स्थित Light House Project (LHP) के दो ब्लॉकों में निर्मित 278 आवासों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियाँ सौंपीं, जो 278 परिवारों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। अपने वीडियो संदेश में श्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों को नए घर मिलने पर बधाई दी और इसे उनके जीवन की नई शुरुआत बताया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव श्री सतेंद्र सिंह भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

LHP अगरतला का निर्माण Light Gauge Steel Framed (LGSF) System और Pre-engineered Steel Structural System जैसी नवाचारपूर्ण तकनीकों के उपयोग से किया गया है। यह परियोजना कम समय में गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और किफायती आवास उपलब्ध कराने में आधुनिक निर्माण तकनीकों की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

देश के पांच अन्य शहरों—चेन्नई, राजकोट, इंदौर, लखनऊ और रांची—में भी Light House Projects सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। इन परियोजनाओं में भारत की विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप अलग-अलग नवाचारपूर्ण निर्माण तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है।

प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार PMAY-U के तहत बड़े पैमाने पर नवाचारपूर्ण निर्माण तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। Global Housing Technology Challenge–India (GHTC-India) के माध्यम से विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्तता के आधार पर 54 नवाचारपूर्ण निर्माण तकनीकों को शॉर्टलिस्ट कर छह व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद छह शहरों में Light House Projects के निर्माण के लिए छह अलग-अलग तकनीकों का चयन किया गया।







Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

24 अक्टूबर, 2026

शहरी परिवहन को मिलेगी नई गति: ओडिशा में PM-eBus Sewa की शुरुआत



24 अक्टूबर 2026 को ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने PM-eBus Sewa योजना के तहत कटक बस डिपो में पहली 25 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ओडिशा सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव (शहरी विकास) श्री सतेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।

ये बसें योजना के तहत ओडिशा के लिए स्वीकृत कुल 400 बसों में से पहली 25 बसें हैं।

16 अगस्त 2023 को शुरू की गई PM-eBus Sewa योजना का उद्देश्य Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के तहत देशभर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के माध्यम से शहरी सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना है। केंद्र सरकार द्वारा ₹20,000 करोड़ की सहायता के साथ इस योजना में बस डिपो और विद्युत अवसंरचना के विकास एवं उन्नयन का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सुलभ बस स्टॉप, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य स्वच्छ, अधिक कुशल और टिकाऊ शहरी परिवहन को प्रोत्साहित करना है, जिसमें संगठित बस सेवा से वंचित शहरों को प्राथमिकता दी गई है।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

24 अक्टूबर, 2026

DMRC को 19वें Urban Mobility India Conference में प्रतिष्ठित 'Award of Excellence' से सम्मानित किया गया



दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) को भुवनेश्वर में आयोजित 19वें Urban Mobility India Conference and Expo में 'Excellence in Innovation and Smart Mobility Solutions' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित 'Award of Excellence' से सम्मानित किया गया।

DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल से यह पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव श्री सतेंद्र सिंह तथा ओडिशा सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की अपर मुख्य सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी भी उपस्थित रहीं। इस सम्मान के माध्यम से शहरी परिवहन में नवाचार और स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों को आगे बढ़ाने में DMRC के योगदान को मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार भारत में शहरी परिवहन के भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी-आधारित, कुशल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के महत्व को भी रेखांकित करता है।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

24 अक्टूबर, 2026

National Urban Conclave एवं Urban Mobility India सम्मेलन में NBCC ने प्रदर्शित की शहरी विकास विशेषज्ञता



श्री तोखन साहू, माननीय राज्य मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित द्वितीय नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव एवं 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026 के दौरान NBCC (India) Limited के स्टॉल का उद्घाटन किया।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इन कार्यक्रमों में नीति-निर्माताओं, शहरी विकास विशेषज्ञों और उद्योग जगत के हितधारकों ने भाग लिया। इस दौरान संधारणीय शहरीकरण, एकीकृत अवसंरचना और प्रौद्योगिकी-आधारित मोबिलिटी समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया।

NBCC की भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए, श्री आशुतोष गौतम, निदेशक (परियोजनाएँ), NBCC ने द्वितीय नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2026 में "Right to Walk – Creating Safe, Walkable and Well-Connected Cities" विषय पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। उन्होंने संधारणीय एवं समावेशी शहरी विकास पर अपने विचार साझा किए और सुरक्षित, पैदल चलने योग्य तथा बेहतर संपर्क वाले शहरी क्षेत्रों के महत्व को रेखांकित किया।

इस भागीदारी के माध्यम से NBCC ने परियोजना प्रबंधन परामर्श, अवसंरचना विकास और शहरी पुनर्विकास के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित की। साथ ही, भारत के शहरी रूपांतरण के दृष्टिकोण के अनुरूप संधारणीय, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरों के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

दैनिक भास्कार
(27 अक्टूबर, 2026)

100 new vehicles will be deployed in the city, two agencies will handle waste collection for 5 years

राहत • बंधवाड़ी में अब तक 42.95 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण

शहर में उतरेंगे 100 नए वाहन, 5 साल तक दो एजेंसियां संभालेंगी कचरा कलेक्शन

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए नगर निगम ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और परिवहन की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत दो एजेंसियों को पांच साल का टेंडर आवंटित किया गया है। क्लस्टर-1 की जिम्मेदारी मैसर्स दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड और क्लस्टर-2 की जिम्मेदारी मैसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है। दोनों क्लस्टरों में कुल 875 वाहन लगाए जाएंगे। इनकी तैनाती 28 अक्टूबर से शुरू करने की योजना है। पहले चरण में 100 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुबंध में दो साल का अतिरिक्त विस्तार देने का प्रावधान भी रखा गया है।

शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा के लिए सोमवार को प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था शुरू होने तक शहर के आठ जोन में 591 वाहनों से कचरा संग्रहण और परिवहन किया जा रहा है। नई व्यवस्था में 675 लाइट कमर्शियल वाहन, 184 ई-रिक्शा और 16 कॉम्पैक्टर शामिल होंगे। इसके अलावा सड़कों की मैनुअल सफाई, नालों की सफाई और झाड़ियों की कटाई के लिए 1,673 कर्मचारी, 47 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और छह जेसीबी तैनात हैं। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग के लिए 25 मशीनें भी उपलब्ध हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बैठक ली थी



बंधवाड़ी में 15.55 लाख मीट्रिक टन कचरा बाकी

बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पुराने कचरे के निस्तारण की समीक्षा में बताया गया कि 20 अक्टूबर तक यहां कुल 58.50 लाख मीट्रिक टन कचरा पहुंचा था। इसमें से 42.95 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 15.55 लाख मीट्रिक टन कचरा अभी बाकी है। अधिकारियों के अनुसार, 16.80 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण के लिए 151.20 करोड़ रुपए के अनुबंध किए गए हैं। वहीं, 8.50 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण के लिए 61.71 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है।

3,815 शिकायतों में से 774 लंबित

बैठक में सड़कों की मरम्मत, नगरिक शिकायतों और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की भी समीक्षा की गई। 24-आवर चैलेंज के तहत मिली 3,815 शिकायतों में से 3,041 का समाधान किया जा चुका है, जबकि 774 शिकायतें लंबित हैं। 100 रोड्स चैलेंज के कार्यों की भौतिक प्रगति 29.3% और 10 आइकॉनिक रोड्स परियोजना की प्रगति 35.8% रही। संपदा योजना के तहत प्रस्तावित 396 किलोमीटर सड़क पुनर्निर्माण में से 223.90 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है।

प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर 2.68 करोड़ का जुर्माना

नगर निगम ने 1 जनवरी से 23 अक्टूबर तक प्रदूषण और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर 12,914 चालान कर करीब 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं, वैप के पहले चरण में 21 से 23 अक्टूबर के बीच 139 चालान कर चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बैठक में सड़कों की नियमित सफाई, पानी के छिड़काव, कचरा संग्रहण और परिवहन की निगरानी तथा प्रदूषण नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अमर उजाला
(24 अक्टूबर, 2026)

देश में 2900 किमी लंबा नमो भारत कॉरिडोर बनाने की तैयारी

भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में किया प्रदर्शनी का उद्घाटन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। देश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों के बीच तेज और बेहतर रेल संपर्क बढ़ाने के लिए करीब 2900 किलोमीटर लंबाई के संभावित नमो भारत कॉरिडोर की पहचान की गई है। इन मार्गों के विकसित होने से कई शहरों और आसपास के क्षेत्रों के बीच सफर आसान हो सकेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने शुक्रवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित उन्नीसवें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से इस योजना और नमो भारत की उपलब्धियों की जानकारी दी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

एनसीआरटीसी के अनुसार, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अक्टूबर 2023 में परिचालन शुरू होने के बाद से अब तक 4.5 करोड़ से अधिक यात्री यात्राएं दर्ज की जा चुकी हैं। इस मार्ग पर रोजाना एक लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। इस सफलता को देखते हुए देश के दूसरे क्षेत्रों में भी नमो भारत जैसी रेल सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। 23 और 24 अक्तूबर को आयोजित सम्मेलन में एनसीआरटीसी ने नमो भारत की सुविधाओं, आधुनिक तकनीक और बेहतर परिवहन व्यवस्था में आए बदलावों को प्रदर्शित किया।

स्टेशनों के आसपास विकसित होंगी आवासीय सुविधाएं

एनसीआरटीसी नमो भारत स्टेशनों के आसपास आवासीय और व्यावसायिक सुविधाएं विकसित करने पर भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को घर, कार्यालय, बाजार और परिवहन की सुविधाएं एक-दूसरे के नजदीक उपलब्ध कराना है। इससे रोजाना आने-जाने में लगने वाला समय कम करने और शहरों के व्यवस्थित विकास में मदद मिल सकती है। प्रदर्शनी में गुरुग्राम नमो भारत स्टेशन और सराय काले खां के आसपास प्रस्तावित विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा हापुड़ेगढ़ और न्यू मेरठ में निर्धारित शहरी क्षेत्रों के विकास की योजनाएं भी रखी गई। इन योजनाओं के तहत बेहतर परिवहन संपर्क के साथ आवासीय और व्यावसायिक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

प्रदर्शनी में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर की जानकारी भी दी गई। यह कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है और इस पर 15 स्टेशन हैं। इसी खूबियों होने पर मेरठ मेट्रो सेवा भी जोड़ी गई है, जिससे क्षेत्रीय रेल और शहर के भीतर की मेट्रो सेवा के बीच बेहतर संपर्क उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक सतीश गोयल ने अतिथियों को नमो भारत की सुविधाओं और परियोजना से जुड़ी जानकारी दी। इसमें शहरी परिवहन को बेहतर बनाने, परिवहन के अलग-अलग साधनों को जोड़ने और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा की जा रही है। एनसीआरटीसी की प्रदर्शनी में नमो भारत के मॉडल, चित्र और अन्य जानकारियां रखी गई हैं। यहां आने वाले लोगों को संबंधित चालकीकरण (एआई) और आपदारी प्रबंधविकास (सीआर) तकनीक के माध्यम से ट्रेन के विकास और रखरखाव की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिल रहा है। एनसीआरटीसी का कहना है कि तेज रेल सेवा, परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच बेहतर तालमेल और शहरों के आसपास योजनाबद्ध विकास से देश के शहरी क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

नई तकनीक से दिखाई ट्रेन की कार्यप्रणाली

इस वर्ष सम्मेलन का विषय 'डिजिटल पुल में शहरी सुगम्यता और बेहतर जीवन' है। इसमें शहरी परिवहन को बेहतर बनाने, परिवहन के अलग-अलग साधनों को जोड़ने और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा की जा रही है। एनसीआरटीसी की प्रदर्शनी में नमो भारत के मॉडल, चित्र और अन्य जानकारियां रखी गई हैं। यहां आने वाले लोगों को संबंधित चालकीकरण (एआई) और आपदारी प्रबंधविकास (सीआर) तकनीक के माध्यम से ट्रेन के विकास और रखरखाव की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिल रहा है। एनसीआरटीसी का कहना है कि तेज रेल सेवा, परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच बेहतर तालमेल और शहरों के आसपास योजनाबद्ध विकास से देश के शहरी क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

अमर उजाला
(27 अक्टूबर, 2026)

दिल्ली में धूल से निपटने के लिए उतरेंगी 70 मशीनें

विनोद डबास

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम (एमसीडी) सड़कों की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने जा रहा है। इसके तहत राजधानी की सड़कों पर 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें (एमआरएसएम) तैनात की जाएंगी। इन मशीनों की तैनाती, संचालन और अगले 10 साल तक रखरखाव पर करीब 923.57 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है। योजना का उद्देश्य सड़कों पर जमा धूल को नियमित रूप से हटाकर उसके कारण होने वाले प्रदूषण को कम करना है। एमसीडी ने मशीनों की तैनाती के लिए परियोजना को तीन पैकेजों में बांटा है। पैकेज-1 में 29, पैकेज-2 में 28 और पैकेज-3 में 13 मशीनें शामिल हैं। तीनों पैकेजों के लिए चयनित एजेंसियों की दरों और उनकी नियुक्ति को मंजूरी देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

एमसीडी 10 साल में खर्च करेगी 924 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रिक और सीएनजी मशीनों से होगी सफाई

परियोजना में डीजल चालित मशीनों के बजाय स्वच्छ ईंधन से चलने वाली मशीनों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। छोटी क्षमता वाली मशीनें इलेक्ट्रिक होंगी, जबकि बड़ी क्षमता वाली मशीनों के लिए इलेक्ट्रिक या सीएनजी का विकल्प रखा गया है। मशीनों से नियमित सफाई होने पर धूल के जमाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

पंजाब केसरी
(23 अक्टूबर, 2026)

डीएमआरसी 991 स्थानों पर 28,454 पौधे लगाएगा

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (पंजाब केसरी) : दिल्ली मेट्रो के फेज-4 कॉरिडोर के निर्माण के दौरान काटे जाने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए दिल्ली में 991 स्थानों पर 28,454 पौधे लगाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) का यह पौधारोपण अभियान मुख्य रूप से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पार्कों में चलाया जाएगा। डीएमआरसी के अनुसार, यह अभियान रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के रिठाला-बवाना औद्योगिक क्षेत्र खंड के निर्माण से जुड़ा है। इसके लिए 291.80 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली निविदा जारी की गई है। पौधे एमसीडी के स्वामित्व वाले क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। यह पहल दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत अनिवार्य प्रतिपूरक पौधारोपण का हिस्सा है। पौधारोपण का काम तीन महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगले छह महीने तक पौधों की देखभाल की जाएगी।

दैनिक जागरण
(25 अक्टूबर, 2026)

695 किमी तक मेट्रो नेटवर्क का होगा विस्तार

- दिल्ली मास्टर प्लान में जाम से निपटने की तैयारी, 200 किमी के साइकिल ट्रैक भी बनेंगे
- बैठक में यातायात प्रबंधन, पार्किंग और पैदल यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 416 किमी से बढ़ाकर 695 किमी किया जाएगा। इसके अलावा 200 किमी लंबे साइकिल ट्रैक विकसित करने की योजना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली के मास्टर प्लान-2047 (एमपीडी-2047) को लेकर हितधारकों की 11वें बैठक में यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग और पैदल यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की।

एलजी तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर आयोजित बैठक में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, एनएचएआई, डीएमआरसी और अन्य संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

मेट्रो और नमो भारत नेटवर्क का विस्तार : एमपीडी-2047 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नमो भारत नेटवर्क को मौजूदा 82 किमी से बढ़ाकर 383 किमी करने की योजना बनी है। इसके अलावा सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट में परिवहन केंद्रों के जरिये मेट्रो सहित विभिन्न साधनों के बीच संपर्क बेहतर बनाने की योजना है। नए शहरी क्षेत्रों तक परिवहन सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने और यात्रियों को अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी देने पर भी जोर है।

सड़कें और पैदल यात्रियों की सुविधाएं होंगी बेहतर

यातायात की बाधाएं दूर करने के लिए नए सड़क नेटवर्क, अंडरपास, एलिवेटेड कारिडोर, सड़क संपर्क की छूटी कड़ियों को जोड़ने और चौराहों में सुधार के प्रस्ताव है। पैदल चलने और साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के साथ सुरक्षित सड़क डिजाइन और दिव्यांगजनों के लिए सुगम फुटपाथ पर भी ध्यान दिया जाएगा। यातायात व पार्किंग प्रबंधन में एआइ के इस्तेमाल किया जाएगा। है। बैठक में हितधारकों ने यातायात प्रबंधन, पार्किंग, बहु-माध्यम परिवहन और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के सुझाव दिए गए हैं।

दैनिक भास्कर
(27 अक्टूबर, 2026)

सिटी एंकर 6 किमी लंबे जलमार्ग पर चलेगा 30 यात्रियों की क्षमता वाला क्रूज

पर्यटन व मनोरंजन का आगाज; छठ पर्व से पहले दिल्ली वालों को यमुना में क्रूज सफारी की मिलेगी सौगात, ट्रायल रन शुरू

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर्यटन और मनोरंजन की नई शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सोनिया विहार से जगतपुर तक विकसित की जा रही यमुना रिवर सफारी का ट्रायल रन और निरीक्षण किया। सरकार की योजना छठ महापर्व से पहले इसे जनता के लिए खोलने की है। इसके तहत दिल्लीवासी मां यमुना के दर्शन के साथ क्रूज में नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना से दिल्लीवासियों का भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव गहरा है। यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।



फूड पार्क और वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे आकर्षण

परियोजना में फूड किऑस्क, रेस्तरां, बच्चों के लिए थिंग्स जोन, म्यूजिक फाउंटेन, वाटर स्पोर्ट्स और फूड पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे अद्भुत परियोजना बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार, डीडीए, दिल्ली सरकार और दिल्ली पर्यटन के साझा प्रयासों से यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि एनजीटी और पर्यावरण संबंधी सभी मानकों का पालन किया गया है। इस बार यमुना तट पर भव्य छठ पूजा की तैयारियां भी की जा रही हैं।

करीब 6 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर फिलहाल 30 यात्रियों की क्षमता वाला क्रूज चलाने की तैयारी है। सोनिया विहार से जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक आने-जाने में लगभग 35 से 45 मिनट लगेंगे। यात्रा पूरी होने के बाद यात्री शुरुआती स्थान पर लौट सकेंगे। ट्रायल रन करीब एक सप्ताह तक चलाने की योजना है। औपचारिक शुभारंभ नवंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है।

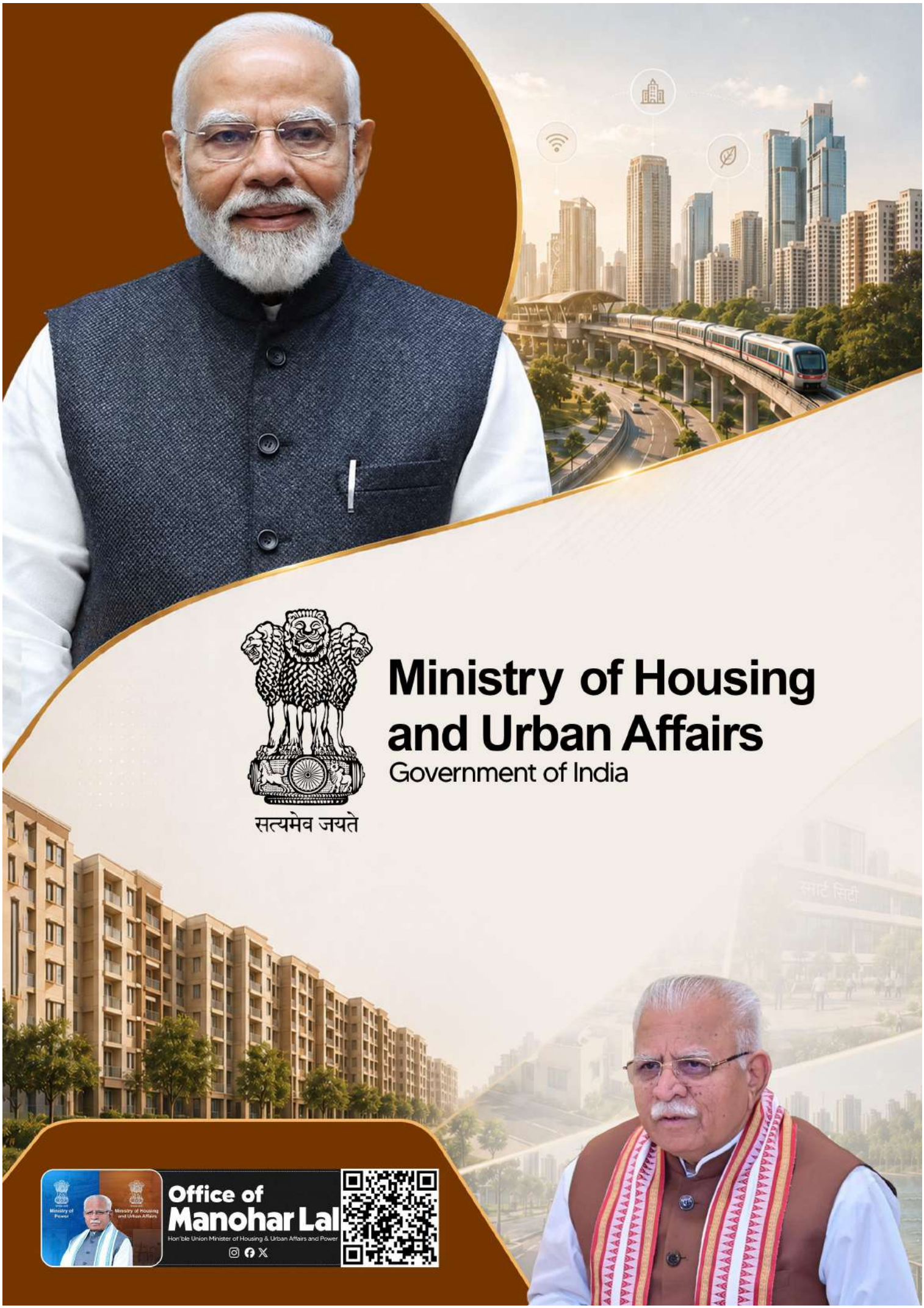
अंतिम ठहराव तय होने के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। परिसर में प्रवेश शुल्क 50 रुपए और क्रूज की पूरी यात्रा का प्रस्तावित किराया 500 रुपए रखा गया है। मुख्यमंत्री ने परियोजना में स्वयंसेवक के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के विभागों की सराहना की। इसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) शामिल हैं।

हिंदुस्तान
(26 अक्टूबर, 2026)

नए रिसाइकल केंद्र बनाए जा रहे

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवददाता। दिल्ली नगर निगम प्रशासन अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर रिसाइकल केंद्रों को स्थापित कर रहा है। इसके जरिए कचरे को कम करने, फिर से उपयोग करने वाले रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल (आरआरआर) केंद्र लगाए जा रहे हैं।

इस केंद्र के सहयोग से घरेलू रद्दी और कम उपयोगी सामग्री की मात्रा को कम किया जाएगा। इसके जरिए उपयोगी वस्तुओं का फिर से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के साथ रिसाइकल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह केंद्रपुराने ढलाव घर का पुनर्विकास प्रक्रिया का हिस्सा बना है।


Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते
Office of
Manohar Lal
Hon'ble Union Minister of Housing & Urban Affairs and Power